कार्यक्रम निश्चित किया गया है। बी०एच०ई०एल० विभिन्न प्रकार के कोयले के लिए सामग्री का मूल्यांकन, हिस्से पुर्जों और गैसीकरण पद्धतियों और साथ ही गैसीकरण हेतु कोयले की उपलब्धता के अनुमानों, उत्पादों के रूप में बाजार में इसकी मांग और इसके आर्थिक मूल्यांकन के संबंध में अध्ययन करेगा, ई०ई०सी० के सहयोगी गैसीकरण प्रक्रिया को इष्टतम बनाने और उपलब्ध कोयला खानों का तकनीकी निर्धारण करने के बाद वाणिज्यिक पैमाने पर इसे लागू करने के निहितार्थों पर अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे। इस कार्यक्रम से विभिन्न प्रकार के उपयोगों के लिए अति उपयुक्त प्रक्रियाओं और डिजाइनों का चयन करने के लिए तकनीकी आर्थिक आंकड़ों के सामने आने की आशा है।

कोयला गैसीकरण तकनीक संयुक्त साइकल प्लांट्स और मैगनेटो हाइड्रो डायनेमिक (एम०एच० डी०) विद्युत जनित्रण प्रणालियों के लिए इस तकनीक का उपयोग करने की सम्भावनाओं को उद्घाटित करेगी जिससे अंततोगत्वा विद्युत जनित्रण प्रक्रिया में काफी अधिक तापीय दक्षता आयेगी। यद्यपि परम्परागत स्टीम साइकल्स में भारत में लगभग 30 प्रतिशत और विकसित देशों में 40 प्रतिशत तक तापीय दक्षता है लेकिन संयुक्त साइकल प्लांटों से इसके लगभग 45 प्रतिशत तक और एम०एच०डी० में यहां तक कि 55–60 प्रतिशत तक बढ़ने की आशा है। इसका अर्थ उपलब्ध कोयले का और अच्छा उपयोग करना होगा और अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम आर्थिक दृष्टि से उचित सिद्ध होगा।

हिमालय के विकास के लिए 'हिमालय' नीति बनाना

*360. डा० रामजी सिंह: क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने अपने चुनाव घोषणापत्र में कहा था कि हिमालय क्षेत्र जैसे पिछड़े और उपेक्षित क्षेत्रों के विकास के लिए एक विशेष योजना तैयार की जायेगी,

(ख) क्या हिमालय के विकास के लिए सरकार का विचार कोई 'हिमालय नीति' तैयार करने का है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) घोषणापत्र में यह कहा गया था कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, हिमालय के क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र और कच्छ आदि जैसे पिछड़े और उपेक्षित क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाएं तैयार की जाएंगी।

(ख) और (ग) हिमालय का क्षेत्र एक जैसा नहीं है, और उसमें बहुत विस्तृत क्षेत्र आता है। उसमें ऐसे राज्य शामिल हैं जो पूरी तरह से पहाड़ी क्षेत्र हैं और ऐसे राज्य भी शामिल हैं जो आंशिक रूप से पहाड़ी हैं और आंशिक रूप से पहाड़ी नहीं हैं। इस पूरे क्षेत्र के लिए एक ही विकास योजना तैयार करना न तो जरूरी है और न ही व्यवहारिक है। परन्तु पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है, और ऐसे विकास के लिए धनराशि निर्धारित की जा रही है।

केन्द्रीय योजना सहायता के आबंटन में इन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है। गाडगिल फार्मूले के अंतर्गत अन्य राज्यों को सहायता आबंटित करने से पहले जो राज्य बिलकुल पहाड़ी हैं उनके लिए संसाधन पहले से अधिकृत कर दिए जाते हैं। जो राज्य आंशिक रूप से पहाड़ी हैं, उनमें राज्य योजना में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक अलग उपयोजना बनाई जाती है। ऐसी उप-योजनाओं में स्कीमों के लिए, राज्य योजना में से आबंटनों के अलावा, विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

1978-83 की योजना के प्रारूप में, यह नीति जारी रखने का प्रस्ताव है। ये कार्यक्रम स्थानीय स्थलाकृति, कृषि-जलवायु और सामाजिक-सांस्कृतिक दशाओं के विशेष रूप से अनुकूल बनाए जाएंगे। नए कार्यक्रमों का उद्देश्य जनसंख्या के गरीब वर्गों को सीधे लाभ पहुंचाना है। ऐसी स्कीमों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनसे अधिक रोजगार पैदा हो और जो स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर आधारित हों।

दिल्ली न्यायालयों से मुकदमों का वापस लिया जाना

*361. श्री चतुर्भुज:
श्री जगदीश प्रसाद माथुर:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के न्यायालयों के ऐसे कितने मामले हैं जिनके वापस लिये जाने के लिए दिल्ली प्रशासन ने, मार्च, 1977 से कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल): 1-3-77 से 31-7-78 तक की अवधि में दिल्ली के न्यायालयों से 727 मामले वापस ले लिये गये हैं।

Journalists accompanied Prime Minister during his visit to U.K.

*363. SHRI K. LAKKAPPA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether attention of Government has been drawn to a report from London in the Times of India dated 18th June, 1978 regarding Prime Minister's visit to Britain and

making reference to a big contingent of journalists who accompanied him,

(b) if so, the details of the journalists, their organisations and the nature of facilities provided to them by Government and

(c) the reaction of Government of India to the report and particularly to the references about journalists?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L K ADVANI) (a) Yes, Sir

(b) A statement is laid on the Table of the House

(c) Considering the number of newspapers in the country and the diverse interests represented by them as well as the importance of the visit of the Prime Minister, the number of journalists who accompanied the Prime Minister cannot be considered large Government do not have any doubts about purpose served by the journalists who accompanied the Prime Minister

Statement

The following 15 journalists accompanied the Prime Minister on his tour to Belgium, U K and U S A

S No	Name	Organisation	Status
1	Shri D V Gandhi	Samachar Bharati (Hindi News Agency)	Chief Editor
2	Shri B P Agarwal	Hindustan Samachar (Hindi News Agency)	General Manager
3	Shri Chandulal Chandrakar	Hindustan (Hindi)	Editor
4	Shri Shantilal Shah	Gujarat Samachar (Gujarati)	Editor
5	Shri V K Madhavan Kutty	Matrubhoomi (Malayalam)	Correspondent
6	Shri D K Joshi	Samaj Cuttack (Oriya)	Correspondent
7	Shri N C Rajkhowa	Dainik Assam (Assamese)	Correspondent
8	Shri N Rama Mohan Rao	Andhra Jyoti (Telugu)	Editor.
9	Shri Hiranmay Karlekar	Hindustan Times (English)	Chief Editor
10	Shri Vishwa Bandhu Gupta	Sun (English)	Editor.
11	Shri Virendra Mohan	UNI (English News Agency)	Correspondent
12	Shri Barun Sen Gupta	Ananda Bazar Patrika (Bengali) Calcutta	Correspondent
13	Shri M S Madhusoodanan	Kerala Kaumudi (Malayalam)	Chief Editor
14	Shri Puran Singh Azad	National Solidarity (English)	Editor
15	Shri Durga Prasad Chaudhury	Nav Jyoti (Hindi) Jaipur	Editor

Pressmen shown against Sl Nos 9 to 15 went on their own and the rest were paid only one way airfare by the Government from New Delhi to New York